बिज़नेस स्टैंडर्ड

अब शोधित जल से ही निकलेगा हल

बीएस संवाददाता

मुंबई में दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार इमारतों में सीवेज वाटर रिसाइकल लगाने का फरमान जारी कर चुकी है। पानी की कमी और प्रशासन की सख्ती को देखते हुए कई कंपनियां वाटर रिसाइकल करने के लिए बेहतरीन तकनीक भी उपलब्ध करा रही हैं। वाटर रिसाइकल से हाउसिंग सोसाइटियों की अतिरिक्त पानी की समस्या तो हल हो रही है लेकिन इससे प्रति वर्ग फुट लागत 12 फीसदी तक बढ़ रही है। इसके बावजूद हाउसिंग सोसाइटियां प्लांट लगवाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिससे सीवेज प्लांट लगाने वाली कंपनियों के पास इस समय काम की भरमार देखने को मिल रही है।

बढ़ती जनसंख्या और पुराने जलस्त्रोतों के खत्म होने की वजह से मुंबई में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। हर दिन 4250 एमएलडी पानी की जरूरत महसूस की जा रही है जबकि मुंबईकरों को सिर्फ 2770 एमएलडी पानी ही मिल पा रहा है और इसमें से भी करीबन 20 फीसदी पानी चोरी एवं रिसाव का शिकार हो जाता है। महानगर पालिका अधिकारियों के अनुसार 2025 तक मुंबई की जनसंख्या 2.64 करोड़ होने की बात कही जा रही है और उस समय 5400 एमएलडी पानी की जरूरत होगी।

महाराष्ट्र सरकार ने इमारतों में वाटर रिसाइकल प्लांट लगाने का फरमान जारी किया है

इस बात को देखते हुए कॉर्पोरेट और हाउसिंग सोसाइटियों से कहा गया है कि वे अपने लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करें जिसमें सीवेज वाटर रिसाइकल सबसे सही उपाय है इसीलिए वाटर रिसाइकल करने की व्यवस्था करना अनिवार्य किया जा रहा है।

जल संचय पर काम करने वाला आयन एक्सचेंज (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों का दावा है कि वितरित किये जा रहे 2770 एमएलडी पानी का 80 फीसदी भाग सेवेज में बदला जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाला पानी प्राप्त करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग दुनिया के कई शहरों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आयन एक्सचेंज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय पोपट कहते हैं कि रिसाइकल किये पानी का उपयोग टॉयलेट फ्लशिंग, बागवानी, भूनिर्माण, वाहनों की धुलाई और कूलिंग टॉवर जैसे कामों के लिए किया जा सकता है जिससे पानी की समस्या खत्म हो सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का खर्च इन्हीं कामों में होता है। पोपट कहते हैं कि लोगों का मानना है कि रिसाइकल प्लांट से लागत बढ़ती है, ये बात सच है कि लागत में प्रति वर्ग फुट 8 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाती है लेकिन आज जो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है उससे लागत अगले दो सालों में वसूल हो जाती है।

आयन एक्सचेंज ने मुंबई की प्रमुख सोसाइटियों में सीवेज रिसाइकल लागने के लिए होने वाले खर्च और उसके फायदे का अध्ययन लोगों के सामने पेश किया है। 480 फ्लैट वाले हाउसिंग सोसाइटी में हर दिन सेकंडरी पर्पज के लिए लगभग 150 एमएलडी पानी की आवश्यकता होती है इसके लिए टैंकर से पानी मांगने पर लगभग 1500 रुपये प्रतिदिन खर्च करने होते हैं, यानी यहां का सालाना बिल 27 लाख रुपये के आसपास होता है। दूसरी तरफ इस सोसाइटी में 40 लाख रुपये की लागत से अगर सीवरेज प्लांट स्थापित किया जाता है, जिसके प्रबंधन में 6 लाख रुपये सालाना खर्च होंगे। यानी सीवेज प्लांट में खर्च होने वाली रकम दो साल में वसूल हो जाती है।

पानी की समस्या को देखते हुए महानगर पालिका पहले ही ऐलान कर चुकी है कि अब इमारतों में वाटर रिसाइकल प्लांट लगाने पड़ेंगे। महानगर पालिका से एक हाथ आगे बढ़कर राज्य सरकार ने इकोफ्रैंडली इमारतें बनाना अनिवार्य कर चुकी है जो 1 अप्रैल से प्रभावी भी हो जाएगा। जिसमें रिसाइकल प्लांट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। सख्त सरकारी रुख और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता की वजह से लोग इस ओर ध्यान भी दे रहे हैं। अब चाहे सरकारी फरमान का असर हो या मुंबईकरों की जागरूकता, सीवेज प्लांट लगाने की मांग तेजी से बढ़ी है।

पिछले तीन महीनों से मुंबई में सीवेज प्लांट लगाने की मांग करीबन 100 फीसदी बढ़ गई है। आयान एक्सचेंज और दूसरी कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि महानगर पालिका ने बागवानी और गाड़ी धुलाई तथा निर्माण कार्य के लिए पानी दिये जाने से मना कर देने की वजह से सीवेज प्लांट लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों के साथ छोटी-छोटी सोसाइटियों में प्लांट लगवाने की तैयारी कर रही है। जिससे वाटर रिसाइकल तकनीक और उपकरण मुहैया कराने वाली कंपनियां इन दिनों चांदी काट रही हैं।